भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1069

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान

1069. **श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलावार कितने विद्यालयों को अनुदान प्राप्त हुआ है;
(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अन्य योजनाएं बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में नया नवोदय विद्यालय खोलने का है;
(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के तहत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	संस्वीकृत राशि (केन्द्रीय भाग) (करोड़ रुपये में)	आबंटित राशि (केन्द्रीय भाग) (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई राशि (केन्द्रीय + राज्य भाग) (करोड़ रुपये में)
2020-21	2730.19	2259.43	4258.73
2021-22	2730.19	2405.82	4443.55
2022-23	3452.19	2138.61	4776.65
2023-24	3560.25	3202.89	5061.21
2024-25	3560.25	1364.62	2925.16*

*दिनांक 31.1.2025 तक पीएफएमएस के अनुसार राज्य के भाग सहित व्यय

(ख): वर्ष 2024-25 में राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की जिलेवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित शिक्षा योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

(i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना-**समग्र शिक्षा** को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, समग्र और एकीकृत पाठ्यचर्या और नवीन शैक्षणिक पद्धतियों को भी शामिल करना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना है।

(ii) विश्व बैंक द्वारा पोषित, **राज्यों हेतु शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना** को राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना और सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। स्टार्स परियोजना स्कूल शिक्षा क्षेत्र हेतु समग्र शिक्षा योजना के प्रयासों में सहायता करता है। इसमें लाभार्थियों के रूप में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षक और छात्र शामिल हैं।

(iii) राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना **प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री)** का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत एनईपी 2020 के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करने के लिए अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में विकसित करने हेतु राजस्थान में 734 विद्यालयों का चयन किया गया है।

(iv) **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं) और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सभी

स्कूल दिवसों में एक बार पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना है।

(घ) से (च): नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है।

नवंबर 2016 में 62 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी देने के साथ ही 100% शहरी आबादी वाले 6 जिलों को छोड़कर इस योजना को स्वीकार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 638 जिलों (दिनांक 31 मई, 2014 तक) को इस योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। राजस्थान के सभी जिले (दिनांक 31.05.2014 तक बनाए गए) नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हाल ही में 28 नए निर्मित/बनाए गए जिलों में नए नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए हैं।

नए नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा स्थायी भवन के निर्माण तक विद्यालय संचालित करने के लिए अपेक्षित अस्थायी भवन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है। नए नवोदय विद्यालयों की स्वीकृति और उन्हें खोला जाना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा 'राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1069 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2024-25 में राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिला	स्कूलों की संख्या
1	अजमेर	1876
2	अलवर	1844
3	बांसवाड़ा	3321
4	बारां	1591
5	बाड़मेर	4856
6	भरतपुर	1775
7	भीलवाड़ा	2905
8	बीकानेर	2113
9	बूंदी	2266
10	चितौड़गढ़	1825
11	चुरू	1443
12	दौसा	1577
13	धौलपुर	1142
14	डूंगरपुर	2737
15	गंगानगर	1952
16	हनुमानगढ़	1110
17	जयपुर	3777
18	जैसलमेर	1310
19	जालोर	1880
20	झालावाड़	1690
21	झुंझुनूं	1544
22	जोधपुर	3603
23	करौली	1451
24	कोटा	1097
25	नागौर	3071
26	पाली	1842
27	प्रतापगढ़	1735
28	राजसमंद	1734
29	सवाई माधोपुर	1104
30	सीकर	2007
31	सिरोही	1011
32	टोंक	1516
33	उदयपुर	4485
	कुल	**69190**